साप्ताहिक

डाक पंजीयनः म.प्र./भोपाल/4-479/2019-21

RNI-MPHIN/2015/72544

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार, 01 मार्च 2021, वर्ष-6, अंक-48

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 8 रुपए

विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने संसदीय कार्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री को किया सचेत, बोले

अन्नदाताओं के साथ नहीं होना चाहिए अन्याय

सरकार और विपक्ष में नोंक-झोंकः आसंदी ने माना-विंध्य के किसान बिजली बिल से परेशान

विशेष संवाददाता, भोपाल

मप्र विधानसभा में अभी बजट सत्र चल रहा है। सरकार और विपक्ष में किसानों को लेकर आए दिन नोंक-झोंक हो रही है। शिवराज जहां एक ओर कांग्रेस सरकार की कर्जमाफी के दावों की पोल खोल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ आरोप पर आरोप थोप रहे हैं। सत्र के पांचवें दिन किसानों को मिल रहे बिजली के मनमाने बिलों पर सदन में जमकर हंगामा हुआ।

जहां मंत्री और विपक्ष के दावों के बीच में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने भी स्वीकार किया कि बिजली की समस्या से मप्र के किसान परेशान हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बिजली के बिलों से विंध्य के किसान सबसे ज्यादा परेशान हैं। विस अध्यक्ष ने संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को सचेत करते हुए कहा कि किसानों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए।

किसान के पास जितने हार्स पावर का मोटर है, उतने का ही बिल आना चाहिए। अगर बताए गए हार्स पावर से अधिक हो तो बिजली कंपनी पर कार्यवाही की जाए। इस पर संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि जैसा विधानसभा अध्यक्ष कह रहे हैं, उसी आधार पर कार्यवाही की जाएगी। वहीं ऊर्जा मंत्री ने भी कहा कि मनमाने बिजली के बिलों की जांच कराई जाएगी।

विस अध्यक्ष ने जो कहा है, हम बिजली बिलों की जांच कराएंगे। दोषियों पर कार्यवाही की जाएगी। विभाग के अधिकारी बिल वसूली के नाम पर मोटर साइकिल नहीं उठाते हैं। मोटर बाइंडिंग के बाद जारी होने वाले बिल को लेकर की जाने वाली शिकायत पर जांच कराई जाती है और पंचनामे की कार्यवाही भी होती है। अगर अधिकारी कार्यालय में नहीं बैठ रहे हैं तो उसके निर्देश जारी करेंगे।

■ प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री

» होशंगाबाद में पायलेट प्रोजेक्ट का श्रीगणेश » नरवाई जलाने पर रोक, क्योंकि फैलता है प्रदूषण

नरवाई से बनेगा कोयला

संवाददाता, भोपाल

दिल्ली में प्रदूषण फैला कर हाहाकार मचाने वाली नरवाई से अब मध्य प्रदेश में कोयला बनाया जाएगा। पायलेट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे होशंगाबाद जिले में शुरू कर दिया गया है। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार का यह बड़ा फैसला है। पंजाब-हरियाणा में नरवाई जलायी जाती है तो दिल्ली में प्रदूषण फैल जाता है। इसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देती थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। नरवाई जलाने पर रोक लगायी गयी। तमाम उपाय सरकार ने किए। अब वही नरवाई मध्य प्रदेश के किसानों के लिए वरदान बनने जा रही है। फसल कटने के बाद बचे इस कचरे से मध्य प्रदेश में कोयला बनाया जाएगा। इसके लिए सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट होशंगाबाद में शुरू कर दिया है। प्रदेश सरकार खेती-किसानी को लाभ का धंधा बनाने के लिए कृत-संकल्पित है। इसके लिए सभी आवश्यक उपाय और व्यवस्था की जाएगी। नरवाई से प्रदेश में कोयला बनाया जाएगा। इसका पायलेट प्रोजेक्ट होशंगाबाद में शुरू किया गया है। सरकार ने इस संबंध में बैठक कर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।

रिजल्ट अच्छा रहा तो प्रदेश में शुरू किया जाएगा

इनका कहना है

नरवाई से प्रदेश में कोयला बनाया जाएगा। अधिकारियों को कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। नरवाई से कोयला बनने से पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होगा। इससे किसानों को आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। पायलेट प्रोजेक्ट होशंगाबाद में लगाया जाएगा। बेहतर परिणाम मिलने पर इसे प्रदेश स्तर पर क्रियान्वित किया जाएगा।

-कमल पटेल, कृषि मंत्री

किसान नरवाई न जलाएं इसके लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। किसानों का जागरूक किया जा रहा है। किसानों को नरवाई जलाने से रोका जा रहा है। नरवाई जलाने से जमीन उर्वरक शक्ति क्षीण होती है। वातावरण भी प्रदूषित होता है। नरवाई को नष्ट करने के लिए वैज्ञानिक तरीके हैं उन्हें अपनाकर किसान परेशानियों से बच सकते हैं।

-जितेंद्र सिंह, उप संचालक, कृषि विभाग

किसानों का होगा फायदा

नरवाई से कोयला बनने पर पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सकेगा। वहीं दूसरी ओर किसानों को भी फायदा होगा। बिजली और गैस की तुलना में कोयले से मिलने वाली ऊर्जा सस्ती होगी। किसानों को नरवाई को जलाने से मुक्ति मिलेगी। किसान आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। अभी होशंगाबाद में इसकी शुरुआत है। रिजल्ट अच्छा रहा तो धीरे-धीरे इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा।

ये थी समस्या : मजदूर न मिलने की वजह से ज्यादातर किसान हार्वेस्टर से गेहूं कटाई कराने लगे हैं। इसमें गेहूं की बाली तक तो कटाई हो जाती पर नरवाई रह जाती है। इसे साफ कराने के लिए किसान ट्रैक्टर से जुताई कराते हैं या आग लगा देते हैं। प्रदेश में खेतों में आग लगाने का चलन तेजी से बढ़ा है। इससे प्रदूषण ज्यादा होता है।

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पूसा कृषि विज्ञान मेले बोले-

भारत कृषि के क्षेत्र में बनेगा बादशाह

भोपाल/नई दिल्ली। किसान कृषि क्षेत्र की मजबूती और प्रगति के लिए संचालित अनेक योजनाओं का लाभ लें। देश का किसान मजबूत होगा तो गांव मजबूत होगा। खेती समृद्ध होगी तो भारत समृद्ध होगा। तभी आने वाले कल में भारत दुनिया के श्रेष्ठ राष्ट्र के रूप में स्थापित हो पाएगा। यह बात केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिल्ली में तीन दिवसीय वार्षिक पूसा कृषि विज्ञान में मेले के शुभारंभ के दौरान कही। यह मेला कृषि कुंभ कहलाता है, जिसमें बड़ी संख्या में देशभर के आम किसान, प्रगतिशील किसान शामिल होते हैं। आत्मनिर्भर किसान की थीम पर आयोजित मेले में तोमर ने कहा कि भारत दुनिया का सिरमौर बने, इसमें सबसे अधिक भूमिका कोई निर्वाह कर सकता है तो वह मेरे देश का अन्नदाता किसान है। हमारे किसानों का परिश्रम है, पूसा जैसे संस्थानों का अनुसंधान है। हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र हैं तो फिर कोई कारण नहीं कि भारतवर्ष इतने बड़े भूगोल के बावजूद कृषि के क्षेत्र में दुनिया में बादशाहत न कर सकें। मंत्री ने आह्वान किया कि किसान नए-नए कृषि अनुसंधान का लाभ लें, खेती को आत्मनिर्भर बनाएं, अपने देश को भी आत्मनिर्भर बनाएं।

स्वर्ण पदक प्राप्त सिविल इंजीनियर ने लाखों की छोड़ी नौकरी, राजकोट में प्रशिक्षण लेने के बाद शुरू किया गौ-पालन

गौ-माता के आशीर्वाद से सिद्धू हो गए आत्मनिर्भर

संवाददाता, इंदौर

स्वर्ण पदक प्राप्त एक सिविल इंजीनियर ने लाखों रुपए की नौकरी छोड़ कर 2016 में उन्होंने स्टार्टअप के रूप में डेयरी फार्मिंग शुरू की। मात्र पौने पांच साल बाद आज उनके डेयरी फार्म में पचास गिरि नस्ल की गाय हैं। वे बेहतर डेयरी फार्म का संचालन तो कर ही रहे हैं, साथ ही नि:शक्त गायों की सेवा भी कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आरजीपीवी से बीई में गोल्ड मेडल प्राप्त रत्नदीप सिंह सिद्धू की। गौ सेवा बीते 11 वर्षों से कर रहे हैं। रत्नदीप

को पढ़ाई के दौरान गायों की स्थिति देखकर गौ सेवा की प्रेरणा मिली। वे गायों की सेवा में जुट गए। यह बात वर्ष 2009 की है, जब वे अपने अपने नाना-नानी के घर गए थे। नाना के साथ आसपास घूमने के दौरान उन्होंने देखा था कि गायें कचरा और प्लास्टिक खा रही हैं। उस दौरान वे आरएसएस की शाखा में भी जाते थे। कुछ लोगों से इसके बारे में बातचीत की। फिर परिवार के साथ सुबह के समय गायों को चारा देने लगे। स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद इंजीनियरिंग की। वर्ष 2012 में इंदौर के निजी कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग में बीई की उपाधि प्राप्त की।

पहले परिजन नहीं थे राजी

गायों की सेवा करने के दौरान कई लोगों ने डेयरी फार्मिंग का सुझाव दिया। इस बारे में माता-पिता से बातचीत की। पहले वे राजी नहीं हुए, क्योंकि वो सिविल इंजीनियरिंग कर रखी थी। धीरे-धीरे परिवार भी राजी हो गया। पौने पांच साल बाद आज गायों से करीब 200 लीटर दूध मिलता है। इससे होने वाली आय की 20 फीसद राशि नजदीकी गौ शालाओं में देते हैं, जिससे वहां गायों की सेवा ठीक से हो सके।

इनका कहना है

खंडवा के एक निजी कॉलेज में पांच लाख सालाना की नौकरी छोड़कर मैं गुजरात के राजकोट स्थित एक गौ-शाला में गया। वहां देशी-विदेशी नस्लों की गायों के बारे में जानकारी प्राप्त की। सालभर वहीं रुका। शुरुआत में तीन गिरि गायों को खरीदने के लिए रिश्तेदारों से पैसे उधार लिए थे। एक लाख 30 हजार रुपए में तीन गाय इंदौर लाया। आज गिरि गायों की संख्या 50 तक पहुंच गई।

रत्नदीप सिद्ध, गौ-पालक, इंदौर

डीजल ट्रैक्टर के मुकाबले साल में किसानों की होगी डेढ़ लाख तक की बचत

- सीएनजी बहुत किफायती, क्योंकि इसमें सीसा नहीं के बराबर
- सीएनजी इंजन के लिए नियमित रखरखाव की जरूरत कम
- किसानों को ईंधन की लागत पर 50 फीसदी तक की बचत

भारत में आया सीएनजी ट्रैक्टर

भोपाल/दिल्ली। भारत में अपनी तरह का पहला सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च हो गया है। सरकार के दावे के मुताबिक इस ट्रैक्टर से प्रदूषण कम होगा और खेती की लागत भी कम आएगी। एक डीजल ट्रैक्टर के मुकाबले किसान इस ट्रैक्टर से साल में एक लाख रुपए बचा सकेंगे। ये ट्रैक्टर जल्द बाजार में उपलब्ध होगा। इस ट्रैक्टर को डीजल से सीएनजी से परिवर्तित किया गया है। ट्रैक्टर को रावमट टेक्नो सॉल्यूशंस और टॉमासेटो अचीले इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से किए गए बनाया गया है। सरकार और कंपनी का दावा है कि डीजल ट्रैक्टर के इस नए रूप से किसान कम लागत में खेती कर सकेंगे। इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। गौरतलब है कि केंद्र सरकार एनर्जी ट्रांजेक्शन में लो-कार्बन पाथ-वे बनाने का प्रयास कर रही है। नवीकरणीय और जैव ऊर्जा पर जोर के साथ एक नया वैकल्पिक ऊर्जा मॉडल बनाया जा रहा है। हरित ऊर्जा पोर्टफोलियो हमारी भविष्य की ऊर्जा मांग को पूरा करेगा।

सीएनजी ट्रैक्टर की खूबियां

- सीएनजी न सिर्फ डीजल के मुकाबले सस्ती है, बल्कि इसमें माइलेज अच्छी मिलता है। यानि डीजल के मुकाबले प्रति घंटे की खपत कम होगी और आउटकम ज्यादा मिलेगा।
- सीएनजी स्वच्छ ईंधन है, इसलिए इसमें कार्बन और अन्य प्रदूषकों की मात्रा सबसे कम है।
- सीएनजी में शीशे की मात्रा शून्य होती है, प्रदूषण कम होता है, इससे ट्रैक्टर के रखरखाव में आसानी होगी और मेंटेनेंस खर्च कम होगा।
- भविष्य का ट्रैक्टर क्योंकि पूरी दुनिया में एक करोड़ 20 लाख वाहन वर्तमान में प्राकृतिक गैस द्वारा ही संचालित होते हैं। इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है।
- यह वेस्ट टू वेल्थ (कचरे से धन) कार्यक्रम का ही एक हिस्सा है, क्योंकि सल की पराली का उपयोग बायो-सीएनजी के उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में किया जा सकता है,
- किसानों को उनके अपने इलाके में बायो-सीएनजी उत्पादन इकाइयों को बेचकर पैसा कमाने में मदद करेगा।
- परीक्षण रिपोर्ट यह बताती है कि डीजल से चलने वाले इंजन की तुलना में रेट्रोफिटेड ट्रैक्टर उससे अधिक/बराबर शक्ति का उत्पादन करता है।
- इससे डीजल की तुलना में कुल कार्बन उत्सर्जन में 70 प्रतिशत की कमी आई है।
- यह किसानों को ईंधन की लागत पर 50 प्रतिशत तक की बचत करने में मदद करेगा, क्योंकि वर्तमान में डीजल की कीमत 80 रुपए प्रति लीटर है, जबकि सीएनजी केवल 42 रुपए प्रति किलोग्राम है।

इनका कहना है

सीएनजी टेक्नोलॉजी डीजल की तुलना में 85 फीसदी कम प्रदूषण करेगा। साथ ही किसान हर वर्ष लगभग 1.5 लाख रुपए ईंधन पर बचत कर पाएंगे। इसके साथ यह किसानों के लिए अतिरिक्त आय का भी साधन बनेगा।

नितिन गडकरी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

भारत में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सबसे ज्यादा इस्तेमाल डीजल का होता है। जबकि देश में करीब 60 करोड़ मीट्रिक टन बायोमास अवेलबल है। सरकार देश में 500 सीबीजी प्लांट्स लगा रही है। जल्द ही सरकार सीबीजी प्रोडक्ट के लिए रिटेल में अनुमति देगी। इथेनॉल प्रोडक्शन में नंबर वन बनने के लिए सरकार पूरी कोशिश करेगी।

धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री

ऊर्जा में आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश

हर साल 1.41 करोड़ टन कार्बन डाई ऑक्साइज उत्सर्जन रोकेगा

आत्मनिर्भर मप्र के रोडमैप पर तेजी से किया जा रहा कार्य

ऊर्जा क्षमता 491 मेगावॉट से अब बढ़कर 5 हजार 42 मेगावॉट

संवाददाता, भोपाल

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्म-निर्भर भारत के स्वप्न को पूरा करने की दिशा में मध्यप्रदेश में तेज गति से कार्य हो रहा है।

ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए नवकरणीय तथा गैर परंपरागत ऊर्जा क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है। पिछले 9 वर्षों में प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में दस गुना बढ़ोत्तरी हुई है। इस क्षेत्र में अब मध्यप्रदेश देश में नेतृत्व की भूमिका में है। वर्ष 2012 में प्रदेश की नवकरणीय ऊर्जा क्षमता 491 मेगावॉट थी, जो अब बढ़कर 5 हजार 42 मेगावॉट हो गई है। प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों से न केवल मध्यप्रदेश ऊर्जा क्षेत्र में आत्म-निर्भरता प्राप्त कर रहा है, अपितु इनसे पर्यावरण की सुरक्षा भी हो रही है।

इस संबंध में प्रदेश में किए जा रहे कार्यों से हर साल लगभग एक करोड़ 41 लाख टन कार्बन डाई ऑक्साइड का उत्सर्जन रोका जा सकेगा। दावा किया जा रहा है कि यह लगभग 43 करोड़ पौधे लगाने के बराबर है।

रीवा में सबसे बड़ी अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना

रीवा में अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना ने अपनी पूरी क्षमता से ऊर्जा उत्पादन शुरू कर दिया है। यह विश्व की बड़ी सौर परियोजना में से एक है। इससे 750 मेगावॉट बिजली प्रतिदिन बन रही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे पैदा होने वाली बिजली प्रदेश की बिजली वितरण कम्पनियों को दिए जाने के अलावा दिल्ली मेट्रो को भी दी जा रही है।

ओंकारेश्वर में अनूठी सोलर फ्लोटिंग परियोजना

ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी पर अनूठी सोलर फ्लोटिंग परियोजना स्थापित की जा रही है। इसके लिए वर्ल्ड बैंक द्वारा सर्वे चालू कर दिया गया है। इसकी लागत तीन हजार करोड़ रुपए होगी और ऊर्जा उत्पादन क्षमता 600 मेगावॉट होगी। योजना को वर्ल्ड बैंक प्रेसीडेंट अवॉर्ड भी दिया गया है।

सिंचाई के लिए सोलर पम्प

मप्र में किसानों को सिंचाई के लिए अनुदान पर सोलर पम्प दिए जा रहे हैं, जिससे सिंचाई के खर्च में काफी कमी आ रही है। प्रदेश के विकास रोडमेप 2023 के अंतर्गत किसानों के खेतों में 45 हजार सोलर पम्प लगाए जाएंगे। अभी तक 22 हजार 673 सोलर पम्प लगाए गए हैं। सोलर पम्प योजना से ऐसे किसान भी लाभान्वित हो रहे हैं, जिनके खेतों तक बिजली नहीं पहुंच रही है। किसान न केवल खुद के उपयोग के लिए सौर ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं बल्कि बिजली कम्पनी को भी बिजली बेच सकते हैं।

इनका कहना है

ऊर्जा के क्षेत्र में दस गुना बढ़ोत्तरी हुई है। इस क्षेत्र में अब मध्यप्रदेश देश में नेतृत्व की भूमिका

में है। आत्म-निर्भर मप्र के रोडमेप के अंतर्गत प्रदेश के नीमच, शाजापुर, आगर, मुरैना, छतरपुर एवं सागर जिलों में सोलर पार्क विकसित किए जा रहे हैं। इन पर 18 हजार करोड़ व्यय होगा। इनकी क्षमता 4 हजार 500 मेगावॉट सोलर बिजली उत्पादन की होगी। सोलर रूफटॉप परियोजनाओं से भी प्रदेश में बिजली उत्पादन का कार्य किया जा रहा है। चालू वर्ष में 3 हजार 642 परियोजनाओं का कार्य होगा।

शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री

बोरिंग उगल रही आग आठ कुओं की तलाश

कुएं में डेढ़ किमी गहराई पर ज्वलनशील गैस निकली

हटा में बोरवेल से पानी के साथ निकल रही मीथेन गैस

दमोह के 24 गांवों में मिला मीथेन का भंडार

बंटी शर्मा, भोपाल/दमोह

बुंदेलखंड में धरती की नीचे कई अमूल्य रत्न छिपे हैं जो आए दिन बाहर भी निकलते रहते हैं, लेकिन अब इस संपदा के साथ साथ पेट्रोलियम पदार्थ और गैस के अपार भंडार होने की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं। दरअसल, दमोह जिले पर पूरी दुनिया की नजर है। इसकी वजह यह है कि यहां 24 गांवों में मीथेन गैस का भंडार मिला है। बोरिंग से पानी की जगह आग निकल रही है। यहां लंबे समय से ओएनजीसी की टीम जांच कर रही है। 1120 करोड़ रुपए खर्च कर 28 कुएं खोदे जा चुके हैं। सेमरा रामनगर गांव में एक कुएं में डेढ़ किमी गहराई पर ज्वलनशील गैस निकली। ओएनजीसी की टीम को क्षेत्र के लोगों ने अपने बोरिंग दिखाए, जिनमें से गैस निकल रही है और आग पकड़ रही है। इसके बाद जांच की गति और तेज की गई। कमता गांव में 12 किसानों के खेतों में बोरिंग में गैस निकल रही है।

देहरादून से आई थी टीम

हटा अनुविभाग के गैसाबाद थाना क्षेत्र के कमता गांव में पिछले दो सालों में होने वाली नलकूपों की खुदाई में गैस भी निकल रही है। इसी के चलते ओएनजीसी देहरादून की टीम को जब इस बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने यहां कई स्थानों पर खुदाई कराई गई जिसमें मीथेन गैस निकली है। हटा विकासखंड मुख्यालय से 27 किमी दूर स्थित ग्राम पंचायत मुहरई में शामिल छोटे से गांव कमता में हुए नलकूप खनन में गंध मिश्रित होने के साथ पानी का स्वाद अच्छा नहीं लग रहा है।

28 कुएं खोदे

1120 करोड़ रुपए खर्च

पानी पीने में भी दिक्कत

गफलू दाहिया ने बताया कि गंध युक्त पानी पीने में भी दिक्कत जा रही है। पूरे गांव में दो बोर ही हैं जिनका पानी पीने में अच्छा लगता है बाकी पानी की बहुत दिक्कत है। कमता गांव से लेकर सुजान तलैया तक के अधिकांश बोरों में गैस निकलने की बात सामने आ रही है। लाखों रुपए खर्च कर बोर कराने वाले किसान खेती में पानी के लिए परेशान ही हैं।

इनका कहना है

अब पुख्ता रूप से गैस मिली है। इसके उपयोग को लेकर कार्ययोजना बनाई जा रही है। काईखेड़ा और पथरिया के बोतराई में भी गैस मिली है। हटा ब्लाक में मीथैन गैस मिली है इसके अलावा कुछ अन्य गैसे भी निकली हैं, लेकिन उनका इतना महत्व नहीं है। यह हटा के लिए अच्छी बात है आने वाले समय में यहां और कुछ नए कार्य किए जाएंगे।

डॉ. एनपी सिंह, रिटायर्ट वैज्ञानिक, ओएनजीसी

पानी में लग गई थी आग

मुन्ना पटैल ने बताया कि दो वर्ष पहले उन्होंने अपने खेत में तीन सौ फीट गहराई पर बोर कराया था। जब उसमें मशीन डाली तो पानी में गंध होने की वजह से एक बार माचिस की तीली जलाकर पानी में लगाई तो पानी में कुछ समय के लिए आग लग गई। इसी गांव के अरविंद पटेल ने दो माह पहले अपने खेत में तीन सौ फीट बोर कराया तो उसमें अलग से गैस जैसी गंध आ रही थी तब उसमें मशीन के साथ एक पाइप अलग से लगा दिया गया ताकि गैस अलग से निकलती रहे। बोर में अलग से लगाए गए इस एक पाइप के पास आग दिखाने से लपटें निकलने लगती हैं।

सौ एकड़ में एक दर्जन बोर

अरविंद पटेल ने बताया कि उसने अपने खेत में तीन सौ फीट बोर कराया और 190 फीट पर मशीन डाली, लेकिन जैसे- जैसे जल स्तर गिरता जा रहा है वैसे ही गैस का रिसाव बढ़ता जा रहा है। हमारे क्षेत्र में लगभग सौ एकड से अधिक क्षेत्रफल में एक दर्जन से अधिक बोर हुए हैं। जिन बोर में 250 फीट तक पानी नहीं निकलता उसके बाद गंध और अमलीय पानी निकल रहा है जिसमें आग लगाने पर लपटे निकलती हैं। हालांकि अभी तक किसी जगह इसकी शिकायत नहीं की है।

सता रहा आग लगने का डर

गांव के ही रामसिंह ने बताया कि उनके खेत के भी बोर में गंध निकली और अचानक बोर के पास बने टपरे में आग लग गई। इसके बाद उसने बोर ही चालू नहीं किया जिससे खेतों की सिंचाई नहीं हो पा रही हैं। देवराज सिंह ने बताया कि उनके बोर में भी पानी के साथ गैस निकलती है, लेकिन मशीन चालू करने में हमेशा डर बना रहता है कि कहीं आग ना लग जाए।

-इसी माह मार्च से सरकार शुरू करेगी प्रक्रिया

प्राइवेट-सरकारी कॉलेज और विवि गांवों को लेंगे गोद

संवाददाता, भोपाल

मध्यप्रदेश सरकार ने पिछड़े गांवों की तरक्की के लिए एक शानदार ढांचा तैयार किया है। इसके तहत प्रदेश के सभी प्राइवेट एवं सरकारी कॉलेज और विश्वविद्यालय अब अपने कैंपस के पास बसे गांवों को गोद लेंगे। गांव को गोद लेने की प्रक्रिया इसी माह मार्च से शुरू हो जाएगी। सरकार का कहना है विश्वविद्यालयों को अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आगे आना चाहिए और समाज के उत्थान में योगदान देना चाहिए। इस वक्त तक कॉलेजों में एनएसएस या एनसीसी यूनिट एक गांव का दौरा करती हैं, सामाजिक कार्य करती है और फिर किसी अन्य कार्य के लिए दूसरे गांव का चयन करती है। अब से, कॉलेज अपने पास के गांव की पहचान करेंगे और उसके सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए काम करेंगे। उनका काम ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं के लाभ के बारे में बताने के अलावा सामाजिक बुराइयों से अवगत कराना भी होगा।

ग्रामीण भारत के होंगे दर्शन

योजना की शुरुआत होने के कारण अब स्टूडेंट और प्रोफेसर को गांव और ग्रामीणों के बीच जाने का मौका मिलेगा जिससे वह ग्रामीण भारत के बारे में जान सकेंगे। इसको छात्र एक मौके की तरह भी देख सकते हैं और रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत अपने इनोवेटिव आइडियाज को गोद लिए हुए गांव में एक्सपेरिमेंट के तौर पर पूरा कर सकते हैं।

समस्याओं की बनेगी रिपोर्ट

मार्च में गांव को गोद लेने के बाद यूनिवर्सिटीज का काम होगा कि वह गांव की तरक्की के लिए अलग-अलग उपाय सोचें और उस पर कार्य करें। इसके साथ ही वह शासन द्वारा जारी की गयी योजनाओं को गांव के हर व्यक्ति तक पहुंचाते हुए उस योजना के द्वारा मिलने वाले लाभ के बारे में बताएंगे। साथ ही गांव की समस्याएं और सरकार की वह योजनाएं जो गांव तक ना पहुंची हो उस पर अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे। रिपोर्ट तैयार करने के बाद उसे उच्च शिक्षा विभाग को भेजना होगा।

इनका कहना है

यह योजना मध्य प्रदेश के पिछड़े गांवों में सुधार लाने के लिए जारी की जा रही है। यूनिवर्सिटी के द्वारा बनने वाली रिपोर्ट के बाद प्रशासन का लक्ष्य उन कमियों को दूर करने का होगा। अब कॉलेज में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को स्टूडेंट्स को पढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा।

■ **डॉ. मोहन यादव,** उच्च शिक्षा मंत्री

आवश्यकता

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर और मुरैना से प्रकाशित

जागत गांव हमार

कृषि और पंचायत पर आधारित साप्ताहिक समाचार पत्र के लिए जिला जनपद स्तर पर संवाददाता चाहिए।

संपर्क करें

जबलपुर, प्रवीण नामदेव-9300034195
शहडोल, गोपाल दास बंसल-9131886277
नरसिंहपुर, प्रहलाद कौरव-9926569304
हरदा, राजेन्द्र बिल्लोरे-9425643410
विदिशा, अवधेश दुबे- 9425148554
सागर, अनिल दुबे-9826021098
दमोह, बंटी शर्मा -9131821040
टीकमगढ़, नीरज जैन -9893583522
राजगढ़, गजराज सिंह मीणा -9981462162
मुरैना, अवधेश दण्डोतिया -9425128418
शिवपुरी, खेमराज मौर्य-9425762414
भिण्ड- नीरज शर्मा-9826266571
खरगौन, संजय शर्मा-7694897272
सतना, दीपक गौतम-9923800013
रीवा-धनंजय तिवारी-9425080670
रतलाम, अमित निगम-70007141120
झाबुआ-नोमान खान-8770736925

कार्यालय का पता:- लाजपत भवन प्रथम तल, आईसीआईसीआई बैंक के पास, एमपी नगर, जोन-1, भोपाल, मप्र,
संपर्क करें- 07554064144, 9229497393, 9425048589

किसानों के हित में नवाचार करती मप्र सरकार

पंकज मित्तल
लेखक जनसंपर्क के अधिकारी हैं

प्रदेश के किसानों को सरकार से मिल रहे संबल से किसानों ने प्रमुख रूप से गेहूं उत्पादन में रिकार्ड कायम किया। मध्यप्रदेश गेहूं उपार्जन में पूरे देश में अव्वल रहा। किसानों के हित में कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन करते हुए ई-ट्रेडिंग का प्रावधान किया गया और किसानों को उपार्जन केन्द्र के साथ ही मंडी के अधिकृत निजी खरीदी केन्द्र और सौदा-पत्रक व्यवस्था के माध्यम से भी फसल बेचने की सुविधा प्रदान की गई।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के किसानों के हित में खेती को लाभप्रद बनाने और किसानों की आय दोगुनी करने के लिये अनेक नवाचार किए हैं। आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण में कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण भागीदारी होगी। कृषि उत्पादन को बढ़ाना, उत्पादन की लागत को कम करना, कृषि उपज के उचित दाम दिलाना और प्राकृतिक आपदा या अन्य स्थिति में उपज को हुए नुकसान में किसान को पर्याप्त क्षतिपूर्ति देना, सरकार के प्रयासों में शामिल हैं।

प्रदेश के किसानों को सरकार से मिल रहे संबल से किसानों ने प्रमुख रूप से गेहूं उत्पादन में रिकार्ड कायम किया। मध्यप्रदेश गेहूं उपार्जन में पूरे देश में अव्वल रहा। किसानों के हित में कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन करते हुए ई-ट्रेडिंग का प्रावधान किया गया और किसानों को उपार्जन केन्द्र के साथ ही मंडी के अधिकृत निजी खरीदी केन्द्र और सौदा-पत्रक व्यवस्था के माध्यम से भी फसल बेचने की सुविधा प्रदान की गई। गेहूं, धान एवं अन्य फसलों के उपार्जन की 33 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खातों में अंतरित की गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मध्यप्रदेश के किसानों को मिल रहा है, जिसके अंतर्गत प्रतिवर्ष किसानों को 6-6 हजार रुपए दिए जाते हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री किसान कल्याण सम्मान निधि योजना की शुरुआत कर किसानों को मध्यप्रदेश शासन की ओर से प्रतिवर्ष 4 हजार रुपए दो बराबर किश्तों में दिए जाना शुरू किया गया। इस प्रकार किसानों को अब कुल 10 हजार रुपए प्रतिवर्ष किसान सम्मान निधि मिल रही है। प्राकृतिक आपदा या किसी अन्य परिस्थिति में किसान की उपज को हुए नुकसान में राहत पहुंचाने वाली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लंबित प्रीमियम जमा कर प्रदेश सरकार ने किसानों को राहत पहुंचाई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सत्ता में आते ही बीमा योजना का लंबित प्रीमियम भरा और प्रभावित किसानों को फसल बीमा राशि दिलवाई गई। लॉकडाउन की विकट स्थिति में एक करोड़ 29 लाख टन गेहूं 16 लाख किसानों से खरीद कर उनके खातों में 27 हजार करोड़ से अधिक की राशि अंतरित की गई।

किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण योजना को पुन: चालू करते हुए किसानों को राहत पहुंचाई गई। इसके लिए सहकारी बैंकों को 800 करोड़ रुपए की राशि भी उपलब्ध करवाई गई, जिससे सहकारी बैंक किसानों को आसानी से कृषि ऋण उपलब्ध करवा सकें।

किसानों की आय को बढ़ाने के लिए बेहतर प्रबंधन और सिंचाई परियोजनाओं पर कार्य किया गया। प्रदेश में अधिक से अधिक क्षेत्र में सिंचाई की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। वर्ष 2020 तक लगभग 40 लाख 27 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं विकसित की गईं। प्रदेश में 19 वृहद, 97 मध्यम और 5344 लघु सिंचाई योजनाओं का कार्य पूर्ण किया गया। इसके साथ ही 27 वृहद, 47 मध्यम और 287 लघु सिंचाई योजनाएं प्रगति पर हैं। प्रदेश में अगले 5 वर्षों में 65 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत मंडला, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया एवं सिंगरौली जिलों में 1707 करोड़ की लागत से 24 हजार 364 भू-जल संरचनाओं का निर्माण कर सीमांत एवं लघु किसानों की 62 हजार 133 हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित की गई।

कोरोना काल में पंचायत एवं ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं में 57 हजार 653 जल- संरचनाओं का निर्माण किया गया। इन जल संरचनाओं में रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत 1835 करोड़ से अधिक लागत के 1007 स्टॉपडेम, 4467 चेक डेम, 19 हजार कपिल धारा कूप, 2588 सार्वजनिक कूप, 1667 पकोलेशन टैंक, 14 हजार 907 हितग्राही मूलक खेत, 2365 सामुदयिक खेत तालाब तथा 4393 नवीन ताबाब बनवाए गए। साथ ही 3115 बावड़ी, तालाब और सामुदायिक जल-संरचनाओं का जीर्णोद्धार तथा सामुदायिक टांका निर्माण सहित 53 हजार 517 जल-संरचनाओं के कार्य किए गए। इसी प्रकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 237 करोड़ की लागत से 2697 खेत तालाब, 726 तालाब, 305 परकोलेशन तालाब, 299 चेकडेम, स्टॉप डेम और 109 नाला बंधान के कार्य किए गए। इन सभी जल संरचनाओं से जहां एक ओर स्थानीय लोगों को कोरोना काल में रोजगार मिला। वहीं भू-जल स्तर में बढ़ोत्तरी के साथ किसानों को खेती में सिंचाई के लिये पानी भी मिल रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा विगत कई वर्षों से सिंचाई बजट में निरंतर वृद्धि भी की जा रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रि-परिषद की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राजस्व पुस्तक परिपत्र में नए प्रावधान जोड़े हैं। इन प्रावधानो में प्राकृतिक प्रकोप, आग लगने तथा वन्य प्राणियों द्वारा मकान नष्ट किए जाने पर आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है। इन नए प्रावधानों से प्रदेश के किसानों को भी लाभ मिलेगा। किसानों को कृषि कार्य के लिए फ्लैट दरों पर बिजली दी जा रही है, जिसमें 22 लाख कृषि उपभोक्ता लाभान्वित हुए हैं। किसानों को खेती के लिए बिजली कनेक्शनों पर 14 हजार 244 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया।

कृषि अधोसंरचना विकास फंड में मध्यप्रदेश देश में सबसे आगे है। अधोसंरचना विकास के लिए आत्मनिर्भर कृषि मिशन का गठन किया गया है। पिछले 10 माह में कृषि विकास एवं किसान-कल्याण के लिये विभिन्न योजनाओं पर 83 हजार करोड़ रुपए से अधिक के हितलाभ दिए गए हैं। किसानों के हित में मंड़ी नियमों में ऐतिहासिक सुधार भी किया गया है। मंडी टेक्स 1.50 प्रतिशत से घटाकर 0.50 प्रतिशत किया गया। कृषि की लागत कम करने, उपादन बढ़ाने तथा उपज का सही दाम किसानों के दिलाने के लिए कृषि उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को मजबूत किया जा रहा है। आगामी वर्षों में एक हजार नए कृषि उत्पादक संगठनों का गठन किया जाएगा।

सरकार द्वारा किसानों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए फसल नुकसानी पर न्यूनतम मुआवजा राशि 5 हजार रुपए की गई है। इस संबंध में राजस्व पुस्तक परिपत्र में संशोधन भी किया गया है। प्रदेश के किसानों को उत्तम गुणवत्ता के खाद-बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस वर्ष किसानों को पर्याप्त खाद उपलब्ध कराए जाने के बाद यूरिया का सरप्लस भंडारण रहा। नकली खाद-बीज बेचने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए उनके लाइसेंस निलंबित और निरस्त भी किए।

बाचा बना देश का पहला सौर-ऊर्जा आत्मनिर्भर गांव

अवनीश सोमकुवर

वर्षों से ऊर्जा की कमी की पीड़ा झेलते-झेलते आखिरकार हम ऊर्जा सम्पन्न बन गए। हमारा गांव बाचा देश का पहला सौर-ऊर्जा आत्म-निर्भर गांव बन गया है। यह बताते हुए अनिल उइके बेहद उत्साहित हो जाते हैं। वे आदिवासी युवा हैं और आदिवासी बैतूल जिले के बाचा गांव के सौर-ऊर्जा दूत भी हैं। बाचा गांव बैतूल जिले के घोड़ाडोंगरी तहसील की खदारा ग्राम पंचायत का छोटा सा गांव है। बाचा गांव सौर ऊर्जा समृद्ध गांव के रूप में देश भर में प्रतिष्ठा अर्जित कर चुका है। यहां की आबादी 450 है। यह मुख्य रूप से आदिवासी बहुल गांव है। अधिकतर गोंड परिवार रहते हैं। हमारे गांव के सभी 75 घरों में सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरणों का उपयोग हो रहा है।

यह बताते हुए खदारा ग्राम पंचायत के पंच शरद सिरसाम कहते हैं कि-हमने बाचा को ऊर्जा की जरूरत में पूरी तरह से आत्म-निर्भर गांव बनाने के लिए संकल्प लिया है। आईआईटी बाम्बे और ओएनजीसी ने मिलकर बाचा को तीन साल पहले ही इस काम के लिए चुना था। इतने कम वक्त में ही हम बदलाव की तस्वीर देख रहे हैं। सभी 75 घरों में अब सौर-ऊर्जा पैनल लग गए हैं। सबके पास सौर-ऊर्जा भंडारण करने वाली बैटरी, सौर-ऊर्जा संचालित रसोई है। इंडक्शन चूल्हे का उपयोग करते हुए महिलाओं ने खुद को प्रौद्योगिकी के अनुकूल ढाल लिया है। खदारा ग्राम पंचायत की पंच शांतिबाई उइके बताती हैं कि- सालों से हमारे परिवार मिट्टी के चूल्हों का इस्तेमाल कर रहे थे। आग जलाना, आंखों में जलन, घना धुआं और उससे खांसी होना आम बात थी। अब हम इंडक्शन स्टोव का उपयोग करने के आदी हो चुके हैं। बड़ी आसानी से इस पर खाना बना सकते हैं। दूध गर्म करना, चाय बनाना, दाल-चावल, सब्जी बनाना बहुत आसान हो गया है। हालांकि हमारे पास एलपीजी गैस है, लेकिन इसका उपयोग अब कभी-कभार हो रहा है। राधा कुमरे बताती है कि पारंपरिक चूल्हा वास्तव में एक तरह से समस्या ही था। मैं अब इंडक्शन स्टोव के साथ सहज हूं। किसी भी समय उपयोग ला सकते है। वन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष हीरालाल उइके कहते हैं कि सूर्य-ऊर्जा के दोहन के प्रभाव को गांव से लगे जंगल पर कम होते जैविक दबाव से स्पष्ट मापा जा सकता है। वन सुरक्षा समिति के प्राथमिक कार्यों का हवाला देते हुए वे बताते हैं कि सभी 12 सदस्य वन संपदा की रक्षा करते हैं। दिन-रात सतर्क रहते है ताकि कोई भी जंगल को नुकसान न पहुंचाए। हमें अवैध पेड़-कटाई और वन्य जीव शिकार जैसी गतिविधियों के बारे में हर समय सचेत रहना पड़ता है। इससे पहले, महिलाएं ईंधन की लकड़ी के लिए प्राकृतिक रूप से गिरी हुई टहनियों को इकट्ठा करने के लिए नियमित रूप से जंगल जाती थीं। लकड़ी बीनने जंगल जाना रोजाना का काम था। अब यह रुक गया है और हमें काफी राहत मिली है। मैं इस गांव का सबसे पुराना मूल निवासी हूं। मैंने करीब से देखा है कि चीजें कैसे बदली हैं। परिवार की आजीविका के लिए तीन एकड़ की खेती पर निर्भर करीब 80 साल के शेखलाल कवड़े याद करते हैं कि-कैसे बाचा मे कोई सड़क नहीं थी। सफाई नहीं थी। बिजली नहीं थी। आज गांव पूरी तरह से बदल गया है।

उन्नत खेतीः मजबूत इच्छा शक्ति से साकार होंगे सपने

डॉ. आनन्द शुक्ल

कृषि हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। मप्र ने बीते वर्षों में कृषि मामले में जो उन्नति की है, उससे उसे नई पहचान मिल रही है। बीते वर्ष 2020 में रबी उपार्जन के मामले में मप्र ने एक करोड़ 29 लाख मीट्रिक टन का रिकार्ड उपार्जन करते हुए पूरे देश में सबससे अग्रणी राज्य का दर्जा हासिल किया है। यह स्थिति रबी के बाद खरीफ के उपार्जन में भी देखने को मिली। बीते वर्षों में उपार्जन को लेकर लगातार बढ़ रहे आंकड़ों पर नजर डाले तो एक बात साफ है कि प्रदेश में कृषि अधोसंरचना के विकास, एवं अन्य आवश्यक सुधान कार्य बीते 15 वर्षों के परिश्रम का परिणाम है। खेती में परिवर्तन के मामले में वर्ष 2003 का साल मध्यप्रदेश के लिए खाफी अहम रहा। राज्य भाजपा सरकार के आने के बाद जिस तेजी से काम, खेती को लेकर किया गया वह अद्भुत और अतुलनीय है। आज उसी का परिणाम है कि मध्यप्रदेश का किसान पंजाब को पीछे छोड़ते हुए देश का सर्वाधिक अन्य उपार्जन केवल मध्यप्रदेश में हो रहा है। इसका एक और जीता जागता प्रमाण यह है कि वर्ष 2004 से 2014 तक केंद्र की मनमोहन सरकार ने लगातार पांच बार कृषि कर्मण ऑवार्ड मध्यप्रदेश को ही दिया। मौजूदा समय में मध्यप्रदेश की झोली में कुल सात कृषि कर्मण आवॉर्ड आ चुके है। इसके साथ ही बीते 5 वर्षों से कृषि के क्षेत्र में लगातार 70 प्रतिशत की अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज कराकर मध्यप्रदेश में मोस्टइनप्रूव्ड राज्य का दर्जा हासिल कर लिया है।

आज मध्यप्रदेश में कृषि को लेकर जो मजबूत स्थिति दिख रही है। उसके लिए यहां की राजनीतिक स्थिरता और सीएम शिवराज के मजबूत इरादों की प्रमुख भूमिका है। चूंकि वह स्वयं किसान परिवार से हैं। इसलिए वह गांव से लेकर सत्ता में आने तक का जो अनुभव है वो प्रदेश की खेती-किसानी और उससे जुड़ी योजनाओं के रूप-रेखा में स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है। सीएम शिवराज ने एक आह्वान किया था कि-खेती बनेगी लाभ का धंधा। इसस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने खेती में लगने वाली लागत दर को कम करने का उपाय भी खोजा। इसके साथ प्रदेश में खेती के लिए सिंचाई सुविधा को एक चुनौती के रूप में लिया। इसका फायदा यह हुआ कि राज्य में सिंचाई का रकवा साढ़े सात लाख हेक्टेयर से बढ़कर अब 40 लाख हेक्टेयर हो गया है। आगामी वर्ष 2025 तक उसे 80 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य है। दरअसल, प्रदेश में खेती की जमीनें सब जगह एक जैसी उपयुक्त नहीं है। इसलिए कई स्थानों पर नहर, बोर और स्प्रींकलर जैसी नई सुविधाओं का सहारा लेना पड़ता है।

इस पूरे प्रसंग में एक बात गौर करने वाली है कि 2018 के आखरी चरणों में प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन हुआ और कांग्रेस की वापसी हो गई। खेती के प्रति कांग्रेस सरकार के उदासीन रवैये का परिणाम यह हुआ कि राज्य कि कृषि विकास दर 41 प्रतिशत से घटकर 13.38 प्रतिशत रह गई। प्रदेश में एक बार फिर खेती बोझ जैसी लगने लगी। दरअसल सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार ने किसानों को दी जाने वाली सहूलियतें बंद कर दी जिसमें मुख्य रूप से शून्य प्रतिशत दिया जाने वाला कर्ज और भावांतर भुगतान जैसी योजनाएं शामिल है। तत्कालीन समय में सिंचाई का रकबा एक हेक्टेयर भी नहीं बड़ा इससे दुर्भाग्य जैसा ही कहेंगे कि वर्ष 2019 में अतिवर्षा तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं की मार प्रदेश के 32 जिलों में पड़ी। किंतु एक भी किसान को 'एक आना' मुआवजे के रूप में नहीं मिला ऐसे में प्रदेश के किसानों की स्थिति क्या रही, कल्पना से परे है। खेती और किसानों के प्रति यह रवैया राज्य को शिवाय पीछे ले जाने के और कुछ नहीं था।

जानकारों की मानें तो मध्यप्रदेश के विकास और उन्नत खेती के लिए दूरदर्शी और मजबूत इच्छाशक्ति की सरकार का होना आवश्यक है। ऐसे में प्रदेश के अन्यदाता किसानों की नजर केवल भाजपा और शिवराज पर आकर टिकती है। खेती की दिशा में हुए निरंतर सुधारों को यदि आंकड़ों की नजर में बात करें तो शिवराज सरकार ने अभी हाल ही में सिंचाई के लिए 50 नवीन परियोजनाओं का जिसकी लागत 384 करोड़ रुपए है। का लोकापर्ण किया है। इसी प्रकार सीप अंबर सिंचाई परियोजना 174 करोड़, सांवेर उद्वहन 2359 करोड़ तथा आसान वैराज्य सिंचाई परियोजना 179 करोड़ जैसी अन्य परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही बंद पड़ी शून्य प्रतिशत पर कर्ज देने की योजना और भावांतर भुगतान जैसी योजना को पुन: चालू किया गया है।

कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्यप्रदेश खेती के मामले में अब पूरे देश का केंद्र बिन्दु बनकर उभर रहा है। खेती और किसान आने बाले दिनों में एक और जहां आत्मनिर्भर बनेगे वहीं दूसरी और मध्यप्रदेश पर टिक गई है। यदि सब कुछ अनुकूल रहा तो आने वाले समय में मध्यप्रदेश खेती के मामले में पूरे देश के लिए एक नया रोल मॉडल बनकर उभरेगा। ऐसे में यह कहना उचित है कि उन्नत और लाभदाई खेती के लिए उदार और मजबूत इच्छाशक्ति की आवश्यकता है।

लोन नहीं चुकाने वाले किसानों को देना पड़ेगा सात फीसदी ब्याज

छिंदवाड़ाः अतिरिक्त ब्याज अनुदान और प्रोत्साहन राशि नहीं मिलेगी

नरेंद्र सोनी, छिंदवाड़ा

प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से अल्पकालीन फसल ऋण लेने वाले किसानों को ड्यू डेट पर चुकाने पर ही शून्य प्रतिशत ब्याज सहायता का लाभ प्राप्त हो सकेगा, जबकि डिफाल्टर किसानों को राज्य शासन एवं केंद्र शासन शासन से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त ब्याज अनुदान तथा प्रोत्साहन राशि की पात्रता नहीं होगी। यह राशि सात प्रतिशत की दर से कृषक को ही ऋण वितरण दिनांक से ड्यू दिनांक तक भुगतान करना होगा। गौरतलब है कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, छिंदवाड़ा से संबद्ध 24 शाखाओं के अंतर्गत 145 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में एक लाख से भी अधिक ऋणी किसान हैं, जो इस समय शाखा व समितियों के माध्यम से प्रदत्त सुविधाओं और शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इस वर्ष 2020-21 में बैंक ने अपनी शाखाओं से संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से अब तक खरीफ सीजन में 365 करोड़ एवं रबी सीजन में 85 करोड़ इस प्रकार कुल 448 करोड़ से भी अधिक का ऋण वितरण कर चुका है। समितियों के कर्मचारी अल सुबह ही किसानों के घर उनके ऋण का हिसाब लेकर पहुंच रहे हैं और उन्हें शासन की योजनाओं और बैंक की शाखाओं व समितियों द्वारा दी जा रही सुविधाओं की जानकारी दे रहे हैं।

शून्य प्रतिशत ब्याज का गणित

प्राथमिक सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को शून्य फीसद ब्याज दर पर अल्पकालीन फसल ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2019 -20 में अल्पकालीन फसल ऋण लेने वाले कृषकों को 0 प्रतिशत ब्याज सहायता योजना के लाभ के संबंध में शासन द्वारा जारी नए निर्देशानुसार उक्त अवधि में समय पर अपना ऋण चुकाने वाले कृषकों को केंद्र सरकार 3 प्रतिशत प्रोत्साहन राज्य सरकार 4 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज सहायता प्रदान करेगी। प्रत्येक कृषक को उपलब्ध सामान्य ब्याज अनुदान राज्य सरकार से 1.50 प्रतिशत तथा केंद्र सरकार से 2 प्रतिशत का भी लाभ प्राप्त होगा, जबकि समय पर अपना ऋण नहीं चुकाने वाले डिफाल्टर कृषकों को केंद्र सरकार से प्रोत्साहन ब्याज सहायता 3 प्रतिशत और अतिरिक्त ब्याज सहायता राज्य सरकार से 4 प्रतिशत प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी, उन्हें प्रत्येक कृषक को उपलब्ध सामान्य ब्याज अनुदान राज्य सरकार से 1.50 प्रतिशत तथा केंद्र सरकार से 2 प्रतिशत ही मात्र प्राप्त हो सकेगा। शेष 7 प्रतिशत की दर से ब्याज राशि स्वयं कृषक को ही ऋण अदायगी तक भुगतान करना होगा।

इनका कहना है

खरीफ सीजन में सहकारी समितियों द्वारा वितरित अल्पकालीन फसल ऋण की अदायगी तिथि 28 मार्च निर्धारित है। इस समय सीमा में ऋण नहीं चुकाने पर ऋणी सदस्यों को शासन की ब्याज सहायता का लाभ नहीं मिल सकेगा। ऐसे में इस योजना के लाभ के लिए आवश्यक है कि ऋणी सदस्य निर्धारित तिथि के पूर्व लिया गया ऋण चुकाएं।

कृष्ण कुमार सोनी, महाप्रबंधक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित

आवक बढ़ी, 10 माह बाद घटा टमाटर का भाव

सब्जी की आवक बढ़ने से गिरी कीमत

होशंगाबाद। शहर के सब्जी बाजार में सब्जी की आवक अच्छी खासी हो रही है। इसी के साथ ही 10 माह बाद भाव में भी कमी देखने को मिल रही है। इस मौसम में इन दिनों हरी सब्जी खरीदने के लिए शहर के हर क्षेत्र से लोग देवा माई परिसर में पहुंच रहे हैं। जो टमाटर बीते दो माह से 20 और 30 रुपए प्रति किलो के भाव बिक रहे थे, अब वही टमाटर 10 रुपए किलो के भाव बिक रहा है। आलू भी दो माह पूर्व 40 रुपए था, अब नया आलू 15 से 20 रुपए प्रतिकिलो के भाव हो जाने से लोगों को राहत मिल रही है। वहीं कोठी बाजार के तय किए गए सब्जी मार्केट में भी कुछ दुकानें लगी हुई थी वहां पर खरीददारी की जा रही थी।

शहर के सतरस्ता क्षेत्र या वीआईपी कहलाने वाले मार्ग पर भी सब्जी की बिक्री बढ़ती जा रही है। गर्मी की शुरुआत होने पर आने वाले समय में कोठी बाजार के व्यवस्थित होने की संभावना फिर बनने लगी है। यहां पर शेड को विस्तार दिया जा चुका है। कुछ समय तक शेड में दुकानें लगने के बाद सर्दी के मौसम में सब्जी विक्रेता शेड में बैठने की बजाय धूप में बैठने में ज्यादा रुचि ले रहे थे। अब धूप तेज होने लगी है तो फिर से शेड के नीचे सब्जी बाजार लगने की उम्मीद है। क्योंकि तेज धूप से बचने के लिए टिन शेड से काफी बचाव हो सकेगा। थोक सब्जी विक्रेता संघ के अध्यक्ष अमीन राइन ने बताया कि स्थानीय किसानों के खेतों से टमाटर व आलू आने से भाव में कमी आ गई है।

-समर्थन मूल्य पर गेहूं व सरसों की होगी बंपर खरीदी

मुरैना में पिछले साल से दो गुने हुए सरसों-गेहूं के पंजीयन

अवधेश डंडोतिया, मुरैना

इस बार समर्थन मूल्य पर गेहूं व सरसों की बंपर खरीदी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि बीते साल की तुलना में इस बार समर्थन मूल्य के पंजीयन कराने वाले किसानों की संख्या दो गुने तक पहुंच गई है। गौरतलब है कि पूर्व में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के पंजीयन की अंतिम तारीख 20 फरवरी थी, लेकिन ई-उपार्जन पोर्टल के जाम होने के कारण पंजीयन की तारीख 5 दिन बढ़ाकर 25 फरवरी कर दी गई थी। जिले में गेहूं के पंजीयन 36272, सरसों के 34258 और चना के लिए 1125 किसानों ने पंजीयन कराया है।

चने का रकबा घटा

इस साल गेहूं व सरसों का रकवा बढ़ा है, यही कारण है, कि पंजीयन कराने वाले किसानों की संख्या भी बढ़ेगी। कृषि विभाग के अनुसार पिछले साल 99022 हेक्टेयर जमीन पर गेहूं हुआ था, जबकि इस साल 99167 हेक्टेयर में गेहूं की फसल खड़ी है। पिछले साल सरसों का रकवा 151574 हेक्टेयर था, जो इस साल बढ़कर 152656 हो गया है। चना की फसल पिछले साल 10700 हेक्टेयर में हुई थी जो, इस बार 6407 हेक्टेयर रह गई है, इसके बाद भी चना बेचने के लिए पिछले साल की तुलना में करीब चार गुना किसानों के पंजीयन हुए हैं।

इनका कहना है

इस बार पिछले साल से दोगुने पंजीयन हो चुके हैं। गेहूं के 36272 और सरसों के 34258 पंजीयन अब तक हो चुके हैं। अभी यह संख्या बढ़ेगी। दोबारा तारीख बढ़ने का फैसला अब तक नहीं हुआ।

बीएस तोमर, जिला नियंत्रक अधिकारी, मुरैना

श्योपुर में चने की जगह गेहूं का कर दिया पंजीयन, बढ़ी परेशानी

लापरवाही के चलते अब फसल नहीं बेच सकेंगे किसान

संवाददाता, श्योपुर

समर्थन मूल्य पर रबी फसल की खरीदी के लिए किए जा रहे पंजीयन में कई किसानों के चने की जगह गेहूं की फसल का पंजीयन कर दिया गया है, जिस कारण अब वह किसान सही फसल का पंजीयन कराने के लिए पंजीयन केंद्रों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन पंजीयन सही नहीं हो पा रहा है। अब पंजीयन की तिथि भी समाप्त हो गई है। ऐसे में किसान समर्थन मूल्य पर अपनी फसल नहीं बेच सकेंगे। रबी फसल की बोवनी के समय सौंठवा हल्का पटवारी द्वारा खेतों में जाकर किस किसान ने कौन सी फसल बोई है, इसका सर्वे किया था। उस समय पटवारी ने कई किसानों का गलत सर्वे कर चने की जगह गेहूं लिख दिया, जिस वजह से अब किसानों के चने का पंजीयन नहीं हो पा रहा है।

चने का नहीं हुआ पंजीयन

नागरगांवड़ा निवासी किसान रामदयाल मीणा ने बताया कि उसने 5 बीघा में चने की फसल बोई थी। उस समय पटवारी ने मौके पर जाकर देखने के बजाए घर पर बैठकर सर्वे कर दिया और चने की जगह खेत में गेहूं की फसल बोना बताकर रिपोर्ट भेज दी। रामस्वरूप मीणा निवासी नागरगांवड़ा के खेत में चने की फसल थी, लेकिन पटवारी ने सर्वे में गेहूं की फसल बता दी। जब किसान समर्थन मूल्य पर फसल बेचने के पंजीयन कराने केन्द्र पर पहुंचे तो उनका चने की फसल का पंजीयन नहीं हो पाया।

पुराने पंजीयन ही कर दिए रिन्यू

किसानों का कहना है कि पटवारी ने बिना जांच करें पुराने पंजीयन को रिन्यू कर दिया, क्योंकि पिछले साल रामदयाल और रामस्वरूप में खेत में गेहूं की फसल थी। किसान फसल गलत हुए पंजीयन को सही कराने के लिए बार-बार पंजीयन केन्द्र व पटवारी के चक्कर काट रहे हैं लेकिन उनकी समस्या का हल नहीं पा रहा है। किसानों ने कलेक्टर से समस्या का निराकरण कराए जाने की मांग की है।

इनका कहना है

पंजीयन गलत होने की शिकायत लेकर कुछ किसान मेरे पास आए थे। हमने तो हमारी सर्वे जांच में सही फसल चढ़ा दी है। अगर पंजीयन गलत हुआ तो इसको सही करा दिया जाएगा।

अरविंद कोटिया, पटवारी, नागरगांवड़ा

सरपंच हंसा जाटव की मेहनत लाई रंग

आदर्श बनी भरभड़िया पंचायत

श्याम जाटव, नीमच

मध्यप्रदेश में एक ग्राम पंचायत है नीमच जिले की भरभड़िया और इसकी सरपंच है एक महिला है। इस गांव में बहुत सारे खास काम होते हैं। दो बार यह गांव प्रधानमंत्री की सांसद आदर्श ग्राम योजना में चयनित हुआ और 24 अप्रैल 2020 को पंचायतीराज दिवस पर प्रदेश में केवल इन्हीं की पंचायत को चाइल्ड फ्रेंडली अवार्ड मिला है और इसमें 5 लाख की राशि भी पुरस्कार के रूप में मिली। पांच वर्षों में इन्होंने अपने गांव की तस्वीर बदल दी है।

पढ़िए इनकी सफलता की कहानी

हंसा जाटव ने एमए हिंदी साहित्य से पोस्ट ग्रेजुएट हैं और बीएएड की डिग्री भी है। अभी वकालत की पढ़ाई कर रही हैं। नीमच जिला मुख्यालय से 9 किलोमीटर दूर भरभड़िया ग्राम पंचायत है। इस पंचायत की सरपंच ने अपने पीहर देवास जिले के क्षिप्रा गांव से आने के बाद ससुराल में रहकर पहले बीए, एमए, बीएड किया और 25 साल की उम्र में सरपंच बन गई।

इस पंचायत में कुल 4200 जनसंख्या है जिसमें 3071 वोटर हैं। ओडीएफ हो चुकी इस पंचायत में आदर्श आंगनबाड़ी से लेकर हर गली में स्ट्रीट लाइटें हैं। सरपंच बनते ही सबसे पहला काम गांव की कक्षा 12वीं में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाली तीन बालिकाओं से से 15 अगस्त का झंडावंदन कराया और सरपंच हंसा जाटव का यह कार्यकाल का पहला झंडावंदन था।

हंसा जाटव ने कहा, हमारी पहली ऐसी ग्राम पंचायत बनी जहां कोई बच्चा कुपोषित नहीं है। हर किसान को उसका मुआवजा मिला। हर ग्रामीण का राशनकार्ड, बैंक अकाउंट है और पात्र हितग्राही महिला को उज्जवला योजना का गैस कनेक्शन दिलाया। पहले साल में 113 लोगों को पेंशन दिलानी शुरू की। ग्राम पंचायत का कोई भी काम हंसा अपनी मर्जी से नहीं करती हैं। वर्ष 2016.17 में 10 ग्राम सभाएं हो चुकी हैं, पंचों की बैठक समय-समय पर अलग से होती रहती है। जब ये सरपंच बनी थीं तो इस पंचायत में कई लोगों के शौचालय नहीं थे और अभी ये पंचायत ओडीएफ यानि खुले में शौच से मुक्त हो चुकी है। हंसा का कहना है, हमने पंचायत में कोई भी काम अलग से नहीं किया, सिर्फ सरकारी योजनाओं को सही से लागू करवाया है।

इनाम की राशि से पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाया: गांव में उत्कृष्ट कार्य करने पर आदिम जाति कल्याण विभाग की ओर से 26 जनवरी 2016 को मप्र के तत्कालीन पर्यटन मंत्री सुरेंद्र पटवा ने मुख्य समारोह में एक लाख की राशि से पुरस्कृत किया और इससे गांव में सूचना के प्रचार प्रसार के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाया। इससे गांव में हर अच्छी और बुरी खबर गांव वालों को लाउड स्पीकर से मिल जाती है और यह स्पीकर गांव के प्रमुख चैराहे पर लगे हुए है। प्रदेश की पहली पंचायत है जिसने यह सिस्टम लगाए।

बैठकों में लिए निर्णय: पंच बैठक में जो भी निर्धारित करते हैं वही काम होता है। शुरू के ढ़ाई साल में बहुत ज्यादा विकास तो नहीं करवा पाए हैं, क्योंकि जब हम प्रधान बने थे उस समय गांव की सड़कें ही पक्की नहीं थी, इसलिए पहले जरूरी काम किए। आखरी के ढाई साल में गांव में सभी जगह पक्की सड़कें बना दी।

हंसा ने अपने प्रयासों से अपनी पंचायत को 2016-17 में कर वसूल करने में अव्वल रही और सरकार ने इसी आधार पर 43 लाख 18 हजार की परफारर्मेंस ग्रांट के रूप में दिए। इस राशि से अजा बस्ती में सामुदायिक भवन की बाउंड्रीवाल, मूत्रालय, पंचायत परिसर में पेवर ब्लाक व सीसी रोड़ का कार्य कराया। इसके अलावा पेयजल के लिए तीन प्रतिशत राशि पंचायत द्वारा पीएचई विभाग को जमा कराए और इससे गांव में 1 लाख लीटर की क्षमता वाली टंकी व कुएं का निर्माण कराया। इसकी लागत 62 लाख आई।

ग्राम संगठन का मुख्यालय बनाया: ग्राम संगठन की स्थापना की जिसमें महिलाओं को लिया गया और और उसका मुख्यालय भी ग्राम पंचायत के सामने स्कूल में रखा है। इस संगठन में गांव के सभी स्व-सहायता समूह की महिलाओं को जोड़ा गया और उन्हें सदस्य बनाया गया। मिड डे मील समिति में आठ महिलाएं है। महिलाओं की भागीदारी पंचायत के कामों में ज्यादा से ज्यादा रहे जिससे उनकी जानकारी बढ़े और वो अपने आप को सशक्त महसूस करें।

पानी की समस्या से लोगों को मिला छुटकारा: ग्राम पंचायत में पानी की बहुत समस्या को देखते हुए पीएचई के माध्यम से नया बोर कराया गया और पाइप लाइन का विस्तार करके बोर का पानी पंचायत के कुएं में संग्रहित किया जा रहा है। हंसा का कहना है कि जिनके पास 10.12 एकड़ जमीन है, हमारी कोशिश है वो हर एक किसान कम से कम एक एकड़ में जैविक खेती जरूर करें। बहुत ज्यादा संख्या में तो नहीं लेकिन किसानों ने जैविक खेती करने की शुरुआत कर दी है।

फोकसः किसानों को उपज का वाजिब दाम मिले

गेहूं के साथ चना, मसूर और सरसों खरीदेगी सरकार

प्रवीन नामदेव, जबलपुर

किसानों को उपज का वाजिब दाम मिले इसके लिए सरकार ने रबी उपार्जन वर्ष की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार गेहूं के साथ किसान चना भी बेच सकेंगे। सरकार ने यह व्यवस्था लागू की है और इस दिशा में प्रयास जारी है कि तेवड़ा मिश्रित चना का उत्पादन बंद कर दिया जाए। किसानों को चना का वाजिब कीमत दिलाकर तेवड़ा दाल के उत्पादन पर प्रभावी रोकथाम की भी कोशिश की जा रही है। किसान रबी सीजन में गेहूं और चना के साथ मसूर और सरसों भी बेच सकेंगे जिसके लिए 63 हजार 354 पंजीयन कराए जा चुके हैं। रबी विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर गेहूं के उपार्जन के लिए 25 फरवरी तक जिले के 63 हजार 354 किसानों ने ई-उपार्जन पोर्टल पर अपना पंजीयन कराया है। पंजीयन के लिए शासन द्वारा 25 फरवरी अंतिम तारीख तय की गई थी। एनआइसी प्रभारी आशीष शुक्ला के अनुसार पंजीयन कराने वाले किसानों के रकबे के सत्यापन की प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है। शासन द्वारा पंजीयन कराने वाले किसानों के रकबे का सत्यापन के लिए 2 मार्च अंतिम तिथि तय की गई है। उन्होंने बताया कि गेहूं के उपार्जन के लिए पंजीयन कराने वाले 63 हजार 354 किसानों के अलावा 9 हजार 993 किसानों द्वारा चना, एक हजार 297 किसानों द्वारा मसूर तथा 129 किसानों द्वारा सरसों के उपार्जन के लिए भी पंजीयन कराया है। इन्हें मिलाकर कुल पंजीकृत 65 हजार 395 किसानों में से 21 हजार 845 किसानों द्वारा एमपी ऑनलाइन कियोस्क, लोकसेवा केन्द्रों एवं कृषि उपज मंडियों में अपना पंजीयन कराया गया है। शेष 43 हजार 550 किसानों का पंजीयन समिति स्तर पर बनाये गये केन्द्रों पर किया गया है। एमआईसी प्रभारी ने बताया कि पंजीयन कराने वाले किसानों के रकबे का सत्यापन चार मापदंडों पर किया जा रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में 50 प्रतिशत से अधिक रकबे का पंजीयन कराने वाले किसान, एमपी ऑनलाइन कियोस्क में पंजीयन कराने वाले किसान, सिकमी में खेती करने वाले पंजीकृत किसान तथा चार हेक्टेयर से अधिक रकबे वाले किसानों का पंजीयन का सत्यापन संबंधित क्षेत्र के एसडीएम और तहसीलदारों द्वारा किया जाएगा।

स्वरोजगार के लिए जैविक खेती प्रशिक्षण का आयोजन

संवाददाता, सीहोर

सीआरडीई कृषि विज्ञान केन्द्र, सेवनियां, सीहोर द्वारा पांच दिवसीय स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण जैविक खेती का आयोजन किया गया। संपूर्ण पांच दिवसीय कार्यक्रम में जिले के 11 कृषक उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण के पश्चात केन्द्र के प्रमुख जेके कनौजिया द्वारा कार्यक्रम के उद्देश्य एवं महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए उपस्थित युवा कृषकों को जैविक खेती के लाभ एवं जैविक संसाधनों के उपयोग के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी दी गयी। पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में संदीप टोडवाल, वैज्ञानिक, मृदा विज्ञान द्वारा युवा कृषकों को जैविक खेती में पोषक तत्व प्रबंधन, केंचुआ खाद उत्पादन, नाडेप कम्पोस्ट, डी कम्पोजर द्वारा खाद तैयार करना, जीवामृत, हरी खाद, जैव उर्वरक का उपयोग एवं जैविक खेती रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आदि की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गयी।

देवेंद्र पाटिल, वैज्ञानिक, फसल उत्पादन द्वारा जैविक खेती में खरपतवार प्रबंधन पर विस्तृत रूप से जानकारी उपलब्ध करायी गयी। दीपक कुशवाह, वैज्ञानिक, पौध संरक्षण द्वारा जैविक विधि से कीट व रोग प्रबंधन को विस्तार पूर्वक कृषकों को समझाया।

डॉ. विमलेश कुमार जैविक खेती में पशुपालन के महत्व पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी। पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में धर्मेन्द्र पटेल, वैज्ञानिक, कृषि प्रसार द्वारा युवा कृषकों को कृषि विज्ञान केन्द्र में प्रदर्षित तकनीकी एवं जैविक कृषक गजराज वर्मा, ग्राम- कुलांश कला के जैविक खेती प्रक्षेत्र एवं जैविक खेती क्लस्टर गुलर छापरी में युवा कृषकों को भ्रमण कराया गया।

गन्ने के अपशिष्ट का ऊर्जा उत्पादन में करें उपयोग

जबलपुर। होमसाइंस कॉलेज में मप्र राज्य परियोजना निदेशालय, उच्च शिक्षा विभाग मप्र शासन, भोपाल द्वारा अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्चुअल कार्यक्रम में मप्र उच्च शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत किया जा रहा है। अंग्रेजी विभाग द्वारा एक दिवसीय संगोष्ठी में एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट विषय पर बात की गई। विशेषज्ञ अनूप कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि गन्ने का जूस उपयोग करने के बाद जो उसका अपशिष्ट पदार्थ बचता है उसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में किया जा सकता है।

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समूह की महिलाएं करेंगी नवाचार

सीहोर। सीहोर जिले में पर्यटन के सृजन के लिए जिला प्रशासन द्वारा एक नई पहल की गई जिसमें सीहोर जिले के धार्मिक एवं रमणीय स्थलों के प्रचार-प्रसार के लिए सीहोर जिले में पुरातत्व, पर्यटन एवं संस्कृति परिषद का गठन किया गया। परिषद द्वारा नर्मदा जंयती के शुभ अवसर पर सलकनपुर पर्यटन ट्रिप का शुभारंभ किया। हर्ष सिंह मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत-सीहोर द्वारा सलकनपुर पर्यटन ट्रिप के लिए बस को हरी झंडी देकर प्रस्थान कराया। सलकनपुर टूरिज्म सर्किट को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए इस ट्रिप की पहल की गई जिसके तहत सीहोर जिले के ग्राम वीरपुर डेम, चीकलपानी, सुरई ढ़ाबा, आमडोह ,बोरदी, सलकनपुर, नकटीतलाई, नीलकछार, आवंलीघाट आदि ग्रामों के कई स्व सहायता समूह सदस्यों के लिए रोजगार के अवसर निर्मित होंगे जिससे उनकी आजीविका में होगी। जिला सीहोर के पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए मप्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के समूह सदस्यों द्वारा इन विभिन्न पर्यटक स्थलों के संरक्षण एवं प्रचार-प्रसार की जिम्मेदारी निभाई जाएगी।

पन्ना में मिला एक पत्ती वाला दुर्लभ पलाश

जंगल में दुर्लभ वनस्पतियों का खजाना

शादिक खान, पन्ना

देशभर में हीरा के लिए प्रसिद्ध मप्र के पन्ना जिले का जंगल वन्यजीवों के साथ-साथ विलुप्ति की कगार में पहुंच चुकी दुर्लभ प्रजाति की वनस्पतियों का भी खजाना है। लेकिन वनों की हो रही अंधाधुंध कटाई व विकास की अंधी दौड़ में प्रकृति प्रदत्त यह अनमोल खजाना तेजी से उजड़ रहा है।

यहां की रत्नगर्भा धरती में पलाश का एक ऐसा दुर्लभ पेड़ मिला है, जिसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कहा जाता है। यह पेड़ जिला मुख्यालय पन्ना से 15 किमी दूर विश्रामगंज गांव के निकट स्थित खेत की मेड़ पर कई दशकों से मौजूद है। यहां से गुजरने वाली रूंज नदी पर सिंचाई बांध का निर्माण चल रहा है और यह पूरा क्षेत्र रूंज डेम के डूब में आता है। अगर समय रहते इस दुर्लभ पेड़ को संरक्षित न किया गया तो इसका वजूद हमेशा के लिए मिट जाएगा। यह पेड़ 50 से 100 वर्ष पुराना होगा अति दुर्लभ प्रजाति का यह पेड़ तकरीबन 25 फीट ऊंचा होगा। एक तरफ बांस के पौधे से घिरा हुआ है। पेड़ का तना काफी मोटा और उसका एक हिस्सा खोखला है, जिससे प्रतीत होता है कि यह पेड़ 50 से 100 वर्ष पुराना होगा।

चित्रकूट के हर्रा गांव में भी मिला था यह पेड़

दीनदयाल शोध संस्थान चित्रकूट के डॉ. रामलखन सिंह सिकरवार ने आठ साल पूर्व लिखा था कि चित्रकूट के जैव विविधता सर्वेक्षण के दौरान हमने एक पत्ती वाले पलाश को सतना जिले में मझगवां तहसील के मुटवा ग्राम व चित्रकूट जिले के हर्रा गांव में खोजा है। इस पेड़ की टहनी में तीन पत्ती की जगह एक पत्ती होती है। इसलिए स्थानीय लोग इसे एक पत्ती दाई कहते हैं। तांत्रिकों की ऐसी मान्यता है कि यह दैवीय वृक्ष है और इसके नीचे खजाना गड़ा होता है।

इनका कहना है

स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर की पांच सदस्यीय टीम ने कुछ वर्षों पूर्व इस क्षेत्र के जंगल का सर्वे किया था। जैव विविधता की दृष्टि से यह पूरा इलाका अत्यधिक समृद्ध है। रूंज डेम के डूब में आने वाला क्षेत्र संकटग्रस्त वन्य प्राणी पैंगोलिन का हैबिटेट भी है। एक पत्ती वाला पलाश अत्यधिक दुर्लभ माना जाता है।

डॉ. विजय पटेल और डॉ. अंजना,
सर्वे टीम के सदस्य

गांव के लोगों ने बचाया

गांव के आदिवासियों का भी यही कहना है कि हम बचपन से इस पेड़ को इसी तरह से देखते आ रहे हैं। क्योंकि यह पेड़ पलाश के दूसरे पेड़ों से भिन्न था, इसलिए गांव के लोगों ने इसे बचा कर रखा, कोई क्षति नहीं पहुंचाई। लेकिन आदिवासी बहुल इस गांव के लोग अब चिंतित हैं कि यह दुर्लभ पेड़ बांध के पानी में डूब कर नष्ट हो जाएगा या फिर काट दिया जाएगा।

कट रहा जंगल

बांध के डूब क्षेत्र में राजस्व भूमि के साथ-साथ बड़ा क्षेत्र जंगल का भी है। तीन तरफ हरी-भरी पहाड़ियों से घिरे इस क्षेत्र में सागौन का घना जंगल है, जिसकी तेजी से कटाई हो रही है। वन अधिकारियों के मुताबिक डूब क्षेत्र में लगभग 48 हजार पेड़ों को काटा जाना है, जिनकी कटाई का ठेका हो चुका है। पेड़ तेजी से काटे जा रहे हैं।

प्रकृति का उपहार

पलाश का पेड़ प्रकृति का एक ऐसा उपहार है जो जीवन को न सिर्फ स्वस्थ बनाता है बल्कि अपने मोहक रंगों से उत्साह, उमंग और हमेशा आनंद में रहने की प्रेरणा देता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पलाश को राज्य पुष्प का दर्जा दिया है। पलाश को ढाक, टेसू, केसू और बुंदेलखंड में इसको छियूल भी कहते हैं।

पहाड़ी में लहलहा रहे 10 हजार पेड़

कटनी। एक ऐसी जगह जहां पहले कभी लोग जाना पसंद नहीं करते थे, अब वहां दस हजार से ज्यादा पेड़ लहलहा रहे हैं। हरियाली ऐसी है कि सुबह-शाम लोग परिवार के साथ यहां आते हैं। जागृति संस्था के दस से बारह सदस्यों की मेहनत और लगन से यह सब संभव हुआ है। 2009 में शहर के बीचोंबीच एक पहाड़ी की नौ एकड़ जमीन तत्कालीन कलेक्टर एम शैलवेंद्रम ने पर्यावरण संरक्षण की गतिविधियों के लिए जागृति संस्था को दी थी। संस्था संस्थापक डॉ. संजय निगम अब दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी जिद ने पहाड़ी को हराभरा कर दिया। डॉ. निगम ने 2009 में पार्क के विकास की शुरुआत दो सौ रुपए में पेड़ों को गोद देकर शुरू की थी। वे कहते थे कि दो सौ रुपए दें। एक पेड़ खुद लगाएं और उसे गोद लें। उनका मानना था कि इससे पर्यावरण के प्रति जागरुकता आएगी। इसके बाद लोग आते गए और कारवां बनता गया। पूरे कटनी शहर ने उनका साथ दिया।

प्रशासन व जन सहयोग से बना 65 एकड़ में पार्क

मुहिम में जुड़े कलेक्टर

मुहिम में कलेक्टर एम शैलवेंद्रम भी जुड़ गए। इसके लिए पर्यावरण संधारण समिति बनाई। इसके पदेन अध्यक्ष कलेक्टर के रूप में वे खुद बने और पार्क संरक्षण का जिम्मा जागृति संस्था को मिला। इसके बाद 2018 में कलेक्टर केवीएस चौधरी के आने के बाद पार्क के विकास ने गति पकड़ी। इसके बाद 2019 में आए कलेक्टर एसबी सिंह ने भी पार्क के विकास में रुचि दिखाई। आज पार्क के पास 65 एकड़ जमीन है।

दो बार चले अभियान

जुलाई 2018 में 2200 और जुलाई 2019 में पांच हजार से ज्यादा पौधारोपण हुआ। कड़ी मेहनत के बाद अब यहां 10 हजार से ज्यादा पेड़ हैं। सदस्यों ने करीब दस साल में पहाड़ी को हरा-भरा कर दिया है।

पार्क से शहर के लोगों को शुद्ध हवा मिल रही है। संस्था का कार्य सराहनीय है। लोगों को अधिक से अधिक पौधरोपण करना चाहिए।
- **प्रियंक मिश्रा,** कलेक्टर, कटनी

» रायसेन में 120 बेसहारा गायों को मिला बसेरा » दो माह में बिना सरकारी मदद शुरू की गौ शाला

ग्रामीणों ने बनाई गौ-शाला, फसल नुकसान और सड़क दुर्घटना घटी

» जैविक खाद के लिए लोग ले जा रही गौ-मूत्र-गोबर

» कमलेश की कोशिश रंग लाईं, गौ-शाला के लिए जसवंत ने दी भूमि

» किसी ने लकड़ी, तिरपाल तो किसी ने की चारा-पानी की व्यवस्था

» सड़क पर गायों के झुंड अब नहीं बैठते इससे दुर्घटनाएं कम हो गईं

बृजेश ठाकुर, रायसेन

जिले की सिलवानी तहसील के ग्राम जैथारी में ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से निराश्रित गायों के लिये गौ-शाला बनाकर एक अनुपम उदाहरण पेश किया है। गौ-शाला से 120 गायों को न केवल सहारा मिला है, बल्कि खेतों में होने वाले फसल नुकसान और सड़क दुर्घटनाओं में काफी कमी आयी है।

दरअसल, किसी ने जमीन का टुकड़ा दिया तो किसी ने शेड बनवा दिया और बन गई चंदन पिपलिया में गौ शाला। यह सब कुछ बिना सरकारी मदद के एक युवा की पहल पर हुआ। दो माह पहले दो गायों से शुरू किया गया यह पुण्य प्रकल्प अब 120 गायों की देखभाल तक पहुंच गया है। इस युवा की पहल से प्रेरित होकर गांव के लोग भी मदद के लिए आगे आ गए हैं।

दान में मिली जमीन

सिलवानी तहसील के चंदन पिपलिया में युवा कमलेश लोधी ने बेसहारा गायों को सड़क हादसों, भूखों मरने और बीमार होने से बचाने की शुरुआत दो-तीन गायों से की थी। पहले स्वयं के खर्च से शेड बनाकर गायों का पालन-पोषण किया। उससे प्रेरित होकर अन्य ग्रामीण भी सहयोग करने आगे आए। गांव के ही प्रताप सिंह धाकड़ ने अपने खलिहान की करीब एक हजार वर्गफीट जमीन गौशाला के लिए दान दे दी है।

गौसेवक भी रखा

गायों को भूसा-पानी उपलब्ध कराने में आधा दर्जन से ज्यादा ग्रामवासी आगे आए। ग्रामीणों की दान राशि से ही गौशाला में गायों की नियमित रूप से देखभाल हो रही है। गोबर-मूत्र की सफाई के लिए तीन हजार रुपए महीने के मेहनताना पर एक गौसेवक भी रख लिया है।

ऐसे हुई गौशाला की शुरुआत

ग्राम में स्कूल संचालित करने वाले कमलेश लोधी ने बताया सड़क पर बेसहारा व बूढ़ी गाय हादसे का शिकार हो जाती थीं। कई बार ये खेतों में घुसकर फसलों को नुकसान पहुंचातीं तो किसानों के बीच विवाद होते थे। खेत से भगाए जाने पर पॉलीथिन व कचरा खाकर बीमार भी हो जाती थीं। जब हमने यह दुर्दशा देखी तो दो-तीन बेसहारा गायों का पालन शुरू किया। हमारे काम की लोगों ने सराहना की और देखते ही देखते कारवां जुड़ गया। अब गौशाला में ग्रामीणों के सहयोग से 120 बेसहारा गायों का पालन रहा है। ग्रामीण बढ़चढ़ कर सहयोग करने के लिए आगे आ रहे हैं। गौशाला का गोबर व गौमूत्र लोग खेतों में जैविक खाद के रूप में उपयोग करने के लिए ले जाते हैं।

मध्यप्रदेश का पहला प्राइवेट सीएनजी गैस प्लांट

दिल्ली आईआईटी ने स्थापित किया था प्लांट

गौ-शाला और गैस प्लांट के प्रमुख प्रकाश मंडलोई और विष्णु पाटीदार ने '**जागत गांव हमार**' से खास बातचीत में बताया कि शारदा विहार आवासीय विद्यालय में वर्ष-2001 में गौ-पालन शुरू किया गया था। शुरुआत में 45 घनमीटर क्षमता का गोबर गैस प्लांट शुरू किया गया था। फिर प्लांट में दिल्ली आईआईटी की तकनीकी टीम ने सीएनजी गैस का नया प्लांट स्थापित किया। तभी से सीएनजी छात्रावास, कर्मचारियों के लिए भोजन पकाने में नई विधि से इस्तेमाल हो रही है। यहां एक हजार से ज्यादा बच्चों के लिए प्रतिदिन लगभग दो हजार से ज्यादा रोटियां, सब्जी, दाल पकाई जाती है। चार-पांच साल पहले 100 घनमीटर क्षमता का बॉयो सीएनजी गैस प्लांट शुरू किया गया। वर्तमान में गौ-शाला में तीन सौ से ज्यादा गाय हैं। यहां रोजाना लगभग पांच टन गोबर निकलता है। उसका इस्तेमाल दोनों प्लांट में किया जाता है।

-पूर्व सरसंघचालक के सुदर्शन का सपना हुआ साकार

शारदा विहार आत्मनिर्भर

अरविंद मिश्र, भोपाल

नरेंद्र मोदी सरकार जहां लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देते हुए कार्बन उत्सर्जन कम कर पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करना चाहती है। वहीं केंद्र सरकार की इस मंशा को राजधानी स्थित सरस्वती विद्या मंदिर शारदा विहार आवासीय विद्यालय फलीभूत कर रहा है। केरवा डैम स्थित गौ-शाला में न सिर्फ उन्नत नस्ल की गाय तैयार की जा रही हैं, बल्कि गायों के गोबर से अन्यंत्र उपयोग भी किया जा रहा है। यहां गायों के गोबर से संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानि सीएनजी (कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस) तैयार की जा रही है, जिसका संस्थान में प्रयुक्त होने वाले वाहनों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जा रहा है। यही नहीं, विद्यालय परिसर में स्थित कामधेनु गौ-शाला में गैस प्लांट से निकले हुए रॉमटेरियल से खाद के साथ गौ-काष्ठ भी तैयार किया जा रहा है। यानी यह संस्थान पूरी तरह इकोफ्रेंडली है। खास बात यह है कि यह मध्यप्रदेश का पहला 100 घनमीटर छमता का प्राइवेट बॉयो सीएनजी गैस प्लांट है, जिससे रोजाना 50 किलो बॉयो सीएनजी तैयार की जा रही है। इस ईंधन से गौ-शाला के दो मिनी ट्रक, तीन वैन और दो बस चलाई जा रही हैं।

लोकल फॉर वोकल

- कामधेनु गौ-शाला में बन रही बॉयो सीएनजी
- गैस से बन रहा खाना और चल रहीं स्कूल की बस और अन्य वाहन
- पहले एक दिन में इस्तेमाल होते थे दस एलपीजी गैस सिलेंडर

"मध्यप्रदेश में गौ-शालाओं का बढ़ावा देना चाहिए। जब सीएनजी का उत्पादन होगा तब गौ-शालाएं आत्मनिर्भर होंगी। इस तहर की गौ-शालाएं स्थापित होने किसानों की आमदनी भी बढ़ जाएगी। साथ ही सड़कों पर आवारा घूमने वाली गायों को संरक्षण मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जब लोग सीएनजी का उपयोग करने लगेंगे तब प्रदूषण भी धीरे-धीरे खत्म हो जाएगा। हमारे यहां पहले एक दिन में दस एलपीजी गैस सिलेंडरों का इस्तेमाल होता था। प्लांट स्थापित होने के बाद सीएनजी का ही उपयोग कर रहे हैं।

प्रकाश मंडलोई, गौ-शाला और गैस प्लांट के प्रमुख, शारदा विहार

गुरुकुल की तर्ज पर भोपाल में सरस्वती विद्या मंदिर शारदा विहार आवासीय विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। वास्तव में संस्था आत्मनिर्भर हो चुकी है। मप्र में इस तरह की पहल से किसानों के अच्छे दिन जरूर आएंगे। अखबार के माध्यम से संस्था को मेरा सुझाव है कि सीएनजी प्लांट के रख-रखाव पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। संस्था से समाज को सीख लेने की जरूरत है। शहर की अपेक्षा गांव में बड़े प्लांट अधिक उत्पादन क्षमता के स्थापित किए जा सकते हैं। कामधेनु गौशाला में सीएनजी उत्पादन बड़ी उपलब्धि है।"

मनोकामना शुक्ला, सिविल इंजीनियर, नई दिल्ली

के. सुदर्शन की अहम भूमिका

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पांचवें सरसंघचालक स्व. के सुदर्शन का सपना था कि शारदा विहार विद्यालय पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो। आज यहां की उपलब्धियां यही बयां कर रही हैं कि उनका सपना साकार हो गया। चूंकि विद्यालय परिसर में काफी समय उन्होंने गुजारा है। वो जिस कुटी में रहते थे वो आज भी विद्यमान है।

ऐसे आया आइडिया

शारदा विहार आवासीय विद्यालय के प्रमुख अजय शिवहरे बताते हैं कि पेट्रोल-डीजल से बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए विद्यालय में गाय के गोबर से बॉयो सीएनजी के उत्पादन का ख्याल आया। इसके लिए परिसर में एक करोड़ की लागत से प्लांट तैयार किया गया। इससे न सिर्फ संस्थान में उपयोग होने वाले वाहन प्रदूषण फ्री हो गए, बल्कि संस्थान में खाना बनाने से लेकर अन्य सहूलियतें भी संभव हो सकी हैं। इसमें सबसे बड़ा फासदा संस्थान का इकोफ्रेंडली होना है। पहले संस्थान में हर दिन दस गैस सिलेंडर उपयोग होते थे।

एक किलो दूध में 250 ग्राम घी

कामधेनु गौ-शाला में वर्तमान में 300 से ज्यादा गिरि नस्ल की गाय हैं। पांच एकड़ में फैले परिसर में सिर्फ ढाई एकड़ में सीएनजी प्लांट और गौ-शाला है। यहां से 300 लीटर दूध रोजाना निकलता है। एक किलो दूध में 250 ग्राम घी निकल रहा है। बाजार में गिरि गाय के घी की कीमत 2200 रुपए प्रति किलो है।

एक गाय पर 150 रुपए खर्च

शारदा विहार में रोजाना 60 लीटर गौ-मूत्र एकत्र किया जाता है। गौ-मूत्र का बाजार भाव 160 रुपए प्रति लीटर है। यही नहीं, कैंसर-डायबिटीज वाला गौ-मूत्र अर्क 180 रुपए लीटर बिकता है। संस्थान में फिनाइल गुनाइल के नाम से बनाया जाता है। गौ-मूत्र और गुनाइल की सप्लाई भोपाल, इंदौर, विदिशा, ग्वालियर, जबलपुर सहित अन्य शहरों में की जाती है। यहां एक गाय खाने-पीने पर प्रतिदिन 150 रुपए का खर्च आता है।

हर साल 22 लाख का गौ-काष्ठ

संस्थान में हर साल करीब 22 लाख रुपए के कंडे बेचे जाते हैं। ये कंडे बॉयो सीएनजी प्लांट से निकले गोबर से बनाए जाते हैं। साथ ही इससे खाद भी बनाई जाती है। यहां सीएनजी प्लांट से निकले गोबर से देसी खाद बनाई जाती है, जिसका बाजार भाव प्रति ट्राली करीब 1500 रुपए है।

2.40 लाख की हर माह बचत

शारदा विहार आवासीय विद्यालय में सीएनजी गैस के उपयोग से हर माह दो लाख 40 हजार रुपए की बचत हो रही है। पहले एलपीजी के दस गैस सिलेंडरों का प्रति दिन उपयोग होता था। जिसका बाजार भाव आज के समय में 800 रुपए प्रति सिलेंडर है। राजधानी में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 800 पर पुहंच गई। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत इंदौर में 818.93, जबलपुर में 800.34 और ग्वालियर में 878 रुपए हो गई है।

औषधीय पौधों की खेती

लोकल फॉर वोकल को चरितार्थ करते संस्थान में सब्जी के साथ औषधि पौधे भी तैयार किए जाते हैं। यहां करीब ढाई एकड़ में सब्जी—भाजी और औषधि पौधों की खेती की जाती है। औषधीय पौधों से 60 प्रकार की दवाइयां भी बनायी जाती हैं। यही नहीं, यहां केचुआ खाद भी तैयार की जाती है। जिसकी काफी डिमांड है।

सीएनजी बनाने की विधि

बॉयो गैस प्लांट से निकली गैस को कंप्रेशर की मदद से सघन दबाव के जरिए शुद्धि किया जाता है। फिर उसे एक बडें सिलेंडर में जमा कर लिया जाता है। इसके बाद 14 किलो क्षमता वाले गैस सिलेंडर में भरने के बाद सीएनजी किट लगे वाहनों में इस्तेमाल किया जाता है।

400 घन मीटर प्लांट की योजना

शारदा विहार में आसपास के गांवों और प्रदेश के अन्य जिलों के बच्चे पढ़ते हैं। जो आवासीय विद्यालय में रहते हैं। स्थानीय बच्चों को लाने-ले जाने के प्रबंधन की बसें जाती हैं। उन बसों को भी बॉयो सीएनजी से चलाने के लिए 400 घनमीटर क्षमता का प्लांट स्थापित करने की तैयारी की जा रही है। जिसे जल्द ही मूर्तरूप दिया जाएगा।

खाना बनाने से लेकर रोजगार तक

बॉयो सीएनजी प्लांट से यहां एक हजार बच्चों के लिए भोजन भी तैयार किया जाता है। सीएनजी से वाहन भी चल रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि यहां एक करोड़ रुपए की लागत से तैयार बॉयो सीएनजी प्लांट से करीब 50 परिवारों को प्रत्यक्ष रोजगार भी मिला है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादकः अजय कुमार द्विवेदी, संपर्क-9229497393, 9425048589, ईमेलः- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)